

## संपादकीय

## भरोसे का कत्ल, जब घर ही बन जाए कत्लगाह

भोपाल में बुजुर्गों पर हमले की यह पहली लहर नहीं है। कुछ वर्ष पहले तक शहर में बुजुर्गों की हत्या की घटनाएं छिपुट थीं, अब वे पैटर्न बनती दिख रही हैं। ताजा घटनाएं चीखकर कहती हैं कि खतरा बाहर नहीं, भीतर है। सूरज नगर में 70 वर्षीय रिटायर्ड आईएएस अधिकारी राकेश अग्रवाल को घर में गला रेतकर हत्या कर दी गई। 25 सितंबर को अवधपुरी में 71 वर्षीय रिटायर्ड खनन अधिकारी मोहन चौधरी पर घर में चुसकर हथौड़े से हमला किया गया और लूट की कोशिश की गई। पचास महीने पहले हबीबगंज में एक बुजुर्ग दंपती को किरायेदार और घरेलू सहायक ने मिलकर निशाना बनाया। इन घटनाओं में एक समानता है, हमलावर कोई अनजान नहीं था। वह वही था जिसे घर में प्रवेश और भरोसा मिला था।

पुलिस के बहीखाते में भरोसे की कमी वेरिफिकेशन के आंकड़ों में दिखती है। कोलार में दो महीने में 450, अशोक गार्डन में 115, गोविंदपुरा में दो महीने में 200, बागसेवनिया में छह महीने में 1,000, हबीबगंज में छह महीने में 500 से ज्यादा और टींटी नगर में किरायेदारों के 124 वेरिफिकेशन हुए, जबकि केयरटेकर का सिर्फ एक आवेदन हुआ। यह आंकड़ा बताता है कि सत्यापन को लेकर अब भी गंभीर लापरवाही है। लोग सोचते हैं कि वेरिफिकेशन से पुलिस की पूछताछ होगी, किरायेदार नाराज होगा या घरेलू सहायक काम छोड़ देगा। यही छोटी सोच बड़े अपराध को जन्म देती है।

पहले संयुक्त परिवार थे, घर में चार आंखें हमेशा पहरा देती थीं। अब एकल परिवार हैं। बच्चे बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली में हैं, माता-पिता भोपाल में अकेले हैं। इसी अकेलेपन का फायदा अपराधी उठाता है। वह पहले भरोसा जीतता है, फिर घर की व्यवस्था और कमजोरियाँ समझता है और एक दिन लुटेरा बन जाता है। 2015 से 2020 के बीच मध्य प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अपराध में करीब 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी और 60 प्रतिशत वारदातों में आरोपी घर का जाना-पहचाना निकला था।

इस भरोसे के कत्ल को रोकने के लिए वेरिफिकेशन अनिवार्य और आसान बनाा होगा। किरायेदार और घरेलू सहायक का पुलिस सत्यापन ऑनलाइन हो तथा प्रमाणपत्र मकान मालिक को मिले। बिना जांच के केयरटेकर उपलब्ध कराने वाली एजेंसियों को जवाबदेही तय हो। मोहल्ला स्तर पर बुजुर्ग सुरक्षा समितियां बनें और अकेले रहने वाले बुजुर्गों का नियमित हालचाल लिया जाए। सीसीटीवी, पैनिक बटन और थाने से जुड़ा हेल्पलाइन नंबर सुरक्षा को मजबूत कर सकते हैं।

रातीबड़ पुलिस ने एजेंसी संचालक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी ने एजेंसी को जो पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाणपत्र दिया था, वह 2025 में पटियाला नामा पुलिस ने जारी किया था। इसके बावजूद एजेंसी ने पुराने प्रमाणपत्र के आधार पर आरोपी को काम पर रखा और दोबारा वेरिफिकेशन नहीं कराया। यह लापरवाही गंभीर सवाल खड़े करती है।

बुजुर्ग घर की नींव हैं। हमने बच्चों को सीसीटीवी में सुरक्षित कर लिया, लेकिन माता-पिता को भरोसे के हवाले छोड़ दिया। यह कैसी तरक्की है, जहां बेटा बाहर है और हत्यारा भीतर है? वेरिफिकेशन कागज नहीं, जीवन रक्षा का पहला मंत्र है। हर नए चेहरे से पूछना होगा, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं, क्योंकि समय रहते पूछा गया यही सवाल किसी जीवन को बचा सकता है।

### आजकल

## हारी सीटों का गणित और सत्ता का मनोविज्ञान

**भाजपा** के लिए चेतावनी का संकेत है। पार्टी ने उन 66 सीटों को केंद्र में रखा है, जहां वह या तो हार का गणित कम अंतर से जीती है। यह आंकड़ा बताता है कि सत्ता में रहते हुए भी संगठन के भीतर असुरक्षा का भाव है। जो दल 20 वर्षों से सत्ता में हैं, वह यदि हारी हुई सीटों पर फिर लौटता है तो इसका अर्थ है कि वह जमीनी पकड़ ढीली होने को स्वीकार कर रहा है। कम अंतर से जीत का डर बड़ी हार से बड़ा होता है।

राजनीति में कम अंतर से जीती सीटें हारी हुई सीटों से अधिक खतरनाक मानी जाती हैं। हारी हुई सीट पर कार्यकर्ता संघर्ष करते हैं, लेकिन कम अंतर से जीती सीट पर आत्मसंतोष आ जाता है। भाजपा की चिंता यही है कि पांच हजार या उससे कम अंतर से जीती सीटें अगली बार पलट सकती हैं। इसलिए वहां बूथ स्तर तक जीवंत संपर्क की बात हो रही है। यह स्वीकारोक्ति है कि बूथ अब कागज पर मजबूत है, जमीन पर नहीं।

इस मंथन में मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री और संगठन महामंत्री एक साथ बैठे। सत्ता जब लंबी चलती है तो संगठन पीछे छूट जाता है। विधायक और मंत्री अपने क्षेत्र में स्वतंत्र सत्ता बन जाते हैं, लेकिन कार्यकर्ता उपेक्षित महसूस करता है। कार्यकर्ताओं से दूर रहने वाले नेताओं को जिम्मेदारी न देने का संदेश इसी खिंचाव को पाटने की कोशिश है। कम बोलने और बयानबाजी से बचने का निर्देश भी इसी चिंता को दर्शाता है।

कारगुप्त में 20 से अधिक विषयों पर चर्चा हुई। निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, प्रशासनिक समन्वय और  बूथ  प्रबंधन का विस्तार बताता है कि पार्टी कई  मोर्चों पर तैयारी कर रही है। 2027 के निकाय चुनाव को 2028 का सेमीफाइनल मानना इसी रणनीति का हिस्सा है।

हारी सीटों पर लौटने का अर्थ है कि पार्टी को नए सामाजिक समीकरण की जरूरत महसूस हो रही है। इस मंथन का अमृत तभी निकलेगा, जब सत्ता अमीरार से बाहर निकले और कार्यकर्ता को नीति निर्माण में भागीदार बनाए। राजनीति में हार को याद रखना जीत से अधिक महत्वपूर्ण होता है।

#### भाषा  सिर्फ शब्द नहीं, संस्कृति की आत्मा है। आज हर हाथ में मोबाइल है और हर मोबाइल में एआई है। वह झट से एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद कर देता है। अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से बुंदेलखंडी, बुंदेलखंडी से गोंडी, सब कुछ पल भर में हो जाता है। लगता है जैसे दुनिया कितनी छोटी हो गई है, लेकिन इस छोटी होती दुनिया में एक बड़ा डर भी छिपा है कि कहीं इस तेज रफ्तार में हमारी अपनी भाषाएं और बोलियां पीछे न छूट जाएं। भाषा सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं है, वह हमारे त्योहारों, परंपराओं, किस्मों, गीतों और लोक कलाओं को अपने अंदर समेटे रहती है। जब एक भाषा मरती है तो सिर्फ कुछ शब्द नहीं मरते, बल्कि एक पूरी दुनिया मर जाती है। अनुवाद मशीन का है, ईसान का नहीं। एआई अनुवाद करता है, लेकिन समझता नहीं है। वह शब्द को शब्द से बदल देता है, लेकिन भाव को भाव से नहीं जोड़ पाता। हमारे यहां कहा जाता है, सावन के झूले में

मल्हार है, तो एआई उसका शाब्दिक अनुवाद कर देगा, लेकिन उस मल्हार में जो नमी है, जो मिट्टी की खुशबू है, जो मां के आंचल की याद है, वह कहाँ से लाएगा? बुंदेलखंड में जब कोई कहता है कि लाला, तुम तो बौरे हो गए हो, तो उसमें प्यार है, डांट नहीं है। एआई इसे अपमान समझ लेगा। मालवा में जब होली पर फाग गाई जाती है तो उसके सुर में जो मस्ती है, वह किसी डेटा में नहीं मिलती। इसलिए यह सोचना कि एआई हमारी भाषाओं को बचा लेगा, एक भ्रम है। वह तो सिर्फ एक यंत्र है, जो हमारे ज्ञान पर पल रहा है।

एआई को चलाने के लिए डेटा चाहिए और डेटा चाहिए तो अंग्रेजी चाहिए, क्योंकि इंटरनेट का नब्बे प्रतिशत से ज्यादा डेटा अंग्रेजी में है। हिंदी का डेटा भी बहुत कम है और

## नईदुनिया

## दल बदलू राजनीति का आईना और लोकतंत्र की पुकार

पिछले चार बरसों में भारतीय लोकतंत्र ने एक अजीब तमाशा देखा है।111 सांसद और विधायक अपने दल का दामन छोड़कर दूसरा दामन थाम चुके हैं। इनमें 26 लोकसभा सांसद और 78 विधानसभा सदस्य शामिल हैं। और तो और, लाखों कार्यकर्ता भी इस दौड़ में पीछे नहीं हैं। वे भी झंडा बदलने में महारत हासिल कर चुके हैं। ऊपर से देखने पर यह सिर्फ एक राजनीतिक घटना लगती है, लेकिन भीतर झांकने पर यह लोकतंत्र की आत्मा पर चोट है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि दल क्यों बदला गया, सवाल यह भी है कि क्या दिल भी बदला गया? आंकड़ों की जुबानी सत्ता का चुंबक कितना ताकतवर है।

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मस और नेशनल इलेक्शन वॉच ने मिलकर एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट की मानें तो सबसे ज्यादा पलायन एनपीएफ से हुआ है। 32 नेता वहां से निकले। 29 नेता भाजपा में शामिल हुए, 20 नेता एनपीपी के थे, नौ नेता कांग्रेस के थे, आठ नेता शिवसेना शिंदे गुट के थे और बाकी छोटे दलों के थे। यह आंकड़ा साफ बताता है कि जिधर सत्ता का सूरज चमक रहा है, उधर ही सब जा रहे हैं। विचारधारा का सूरज तो कब का डूब चुका है। अब तो सिर्फ सत्ता की रोशनी में ही सबको अपना भविष्य दिखता है।

भाजपा का आंगन सबसे बड़ा क्यों लगता है? इस पूरी भागदौड़ में सबसे ज्यादा जनप्रतिनिधि भाजपा को मिले हैं। 29 जनप्रतिनिधियों में सात राज्यसभा सांसद और 22 विधायक हैं। रिपोर्ट कहती है कि लोकसभा का कोई सांसद अपनी मूल पार्टी छोड़कर भाजपा में नहीं गया,

## सुप्रीम कोर्ट का कड़ा संदेश, बयान नहीं जवाबदेही चाहिए...

## दिल्ली एनसीआर में बढ़ते यौन अपराध पर संज्ञान

#### दिल्ली एनसीआर में बढ़ते यौन अपराध पर संज्ञान



**दिल्ली** एनसीआर में यौन अपराधों की बढ़ती घटनाओं ने अब सर्वोच्च न्यायालय को भी चिंतित कर दिया है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस गंभीर विषय पर स्वतः संज्ञान लिया। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने सुनवाई करते हुए स्पष्ट कहा, केवल नेताओं और अफसरों के बयान काफी नहीं हैं। अब जवाबदेही तय होनी चाहिए। पीठ ने कहा कि अपराधों की रोकथाम में प्रशासनिक और कानून व्यवस्था से जुड़ी जो खामियां हैं, उनकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।

देश भर में हर रोज 81 मामले, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नवीनतम आंकड़े डराने वाले हैं। वर्ष 2024 में देश भर में बलात्कार के 29,536 मामले दर्ज हुए हैं, यानी हर दिन औसतन 81 मामले। यह आंकड़ा बताता है कि स्थिति कितनी भयावह है। 70 साल से कम उम्र में हृदय रोग से होने वाली मौतों में एक तिहाई मौतें समय से पहले हो रही हैं और उससे बड़े कारणों में तंबाकू, हाई बोपी, शुगर, मोटापा, निष्क्रिय जीवनशैली, खराब खांपान और वायु प्रदूषण हैं। लेकिन यौन अपराधों का ग्राफ भी उसी गति से बढ़ रहा है।

दिल्ली पुलिस में दर्ज मामलों का आंकड़ा भी चिंताजनक है। वर्ष 2021 में 2,076 मामले दर्ज हुए। वर्ष 2022 में 2,043 मामले दर्ज हुए। वर्ष 2023 में 2,141 मामले दर्ज हुए। वर्ष 2024 में

#### नईदुनिया

#### नईदुनिया

## जब कुर्सी बड़ी हो जाए तो विचारधारा छोटी लगने लगती है



क्योंकि लोकसभा में तो पहले से ही भाजपा का दबदबा है। राज्यसभा के सातों सांसद पहले आम आदमी पार्टी के टिकट पर आए थे और अब वे खास होकर भाजपा में आ गए हैं। गोवा के आठ कांग्रेस विधायक, गुजरात के चार, हिमाचल के दो और मणिपुर के पांच जेडीयू विधायक भी इसी कतार में हैं। दूसरी तरफ, जिन पार्टियों से लोग भागे हैं, उनमें एनडीपीपी के 25, टीएमसी के 20 और कांग्रेस के 19 नेता हैं। यानी जहां सत्ता की नाव डूब रही है, वहां से सब कूद रहे हैं।

नागालैंड से बंगाल तक एक ही कहानी का अलग मंचन। नागालैंड में 31 विधायकों ने कहा कि हमने दल नहीं बदला, हमने विलय किया है और विधानसभा अध्यक्ष ने भी उनकी बात मान

ली। यह विलय का खेल तो ऐसा है जैसे कोई कहे कि मैंने घर नहीं बदला, बस नाम बदल दिया है। बंगाल में 20 मामले, तेलंगाना में नौ, गोवा और पंजाब में आठ-आठ मामले सामने आए हैं। इससे पता चलता है कि दल बदल की बीमारी किसी एक राज्य की नहीं, बल्कि पूरे देश की है। हर जगह स्क्रिप्ट वही है, बस कलाकार बदल जाते हैं।व्यंग्य के पीछे छिपा गंभीर सवाल, क्या आत्मा भी बिकती है? कल तक जो नेता एक पार्टी के मंच से दूसरी पार्टी को कोस रहा था, आज उसी पार्टी के मंच से उसकी तारीफ कर रहा है। कल तक जो नेता धर्मनिरपेक्षता की दुहाई दे रहा था, आज वह दूसरी ही भाषा बोल रहा है। कुर्ता वही है, टोपी वही है, चेहरा वही है, बस गमछा बदल गया है। इससे बड़ा व्यंग्य और

## व्यंग्य के पीछे छिपा गंभीर सवाल, क्या आत्मा भी बिकती है? कल तक जो नेता एक पार्टी के मंच से दूसरी पार्टी को कोस रहा था, आज उसी पार्टी के मंच से उसकी तारीफ कर रहा है। कल तक जो नेता धर्मनिरपेक्षता की दुहाई दे रहा था, आज वह दूसरी ही भाषा बोल रहा है। कुर्ता वही है, टोपी वही है, चेहरा वही है, बस गमछा बदल गया है।

## वह सोचता है कि मेरे वोट की कीमत क्या है? क्या मेरा वोट सिर्फ सत्ता की मंडी में बिकने के लिए है? कानून की आंखों पर पट्टी और अध्यक्ष की भूमिका पर प्रश्न। दल बदल विरोधी कानून बना तो है, लेकिन उसकी आंखों पर पट्टी बंधी है। दो तिहाई विधायकों के साथ विलय का प्रावधान इस कानून का सबसे बड़ा छेद है। नेता इसी छेद से निकल जाते हैं और कहते हैं कि यह दल बदल नहीं, विलय है। विधानसभा अध्यक्ष, जो खुद किसी दल से आता है, वह भी अपने दल के हित में फैसला देता है। मामला सालों तक अदालत में लटका रहता है और जब तक फैसला आता है, तब तक अगला चुनाव आ जाता है और जनता सब भूल जाती है। इसलिए इस कानून को और सख्त और निष्पक्ष बनाने की जरूरत है। दिल बदलने की असली परीक्षा अभी बाकी है। दिल नहीं, दल बदले, यह बात सौ प्रतिशत सच है। दल तो बदल लिए, लेकिन दिल वहीं अटक़ा है, जहां पहले था। अगर दिल सच में बदलता तो भाषा बदलती, सोच बदलती और काम करने का तरीका बदलता, लेकिन यहां तो सिर्फ मंच बदलता है, विचार वही रहते हैं। इसीलिए जनता को चाहिए कि वह सिर्फ झंडा न देखे, बल्कि दिल भी देखे। अगली बार जब कोई नेता आपके दरवाजे पर वोट मांगने आए तो उससे पूछिए कि आपने पिछली बार किस दल से चुनाव लड़ा था और अब किस दल से आए हैं। अगर उसका जवाब संतोषजनक न हो तो उसे वहीं रोक दीजिए। तभी यह आयाराम-गयाराम की संस्कृति रूकगी और लोकतंत्र फिर से मजबूत होगा।

( नईदुनिया संपादकीय डेस्क )

## पॉश बंगलों के बीच शोरूम का जंगल, सत्तर लाख का पास

## अरेरा की कहानी, घर से दुकान तक



## भोपाल की अरेरा कॉलोनी कभी

नेताओं, उद्योगपतियों, अफसरों की शांत बस्ती कहलाती थी। अब वहां 4,500 घरों में दुकानें चल रही हैं। डॉक्टर का क्लीनिक, वकील का ऑफिस, बुटीक, कैफे और कोचिंग सेंटर, सब घरों में घुस चुके हैं। अब नए मास्टर प्लान ड्राफ्ट 2047 में इस सच्चाई को नियम का नाम दिया जा रहा है। प्रति वर्गफीट 1,556 रुपए की दर से फीस देना हो रही है। बड़े शोरूम के लिए वहां रकम 70 लाख तक जा रही है। जो कारोबार कर रहे हैं, वे अभी से हिसाब लगा रहे हैं, ताकि प्लान लागू होते ही पैसा भरकर वैध हो जाएं।

**बारह मीटर की गली में अस्पताल का सपना**-नए ड्राफ्ट में सड़क की चौड़ाई से व्यवसाय तय किया गया है। 12 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर एक मंजिल पर डॉक्टर, वकील, इंजीनियर को बैठने की अनुमति, 12 से 18 मीटर पर बैंक, मेडिकल स्टोर और डे केयर सेंटर, 18 से 24 मीटर पर नर्सिंग होम, होटल, रेस्टोरेंट और कोचिंग, 24 से 30 मीटर पर सर्विस सेंटर और सारी मिश्रित गतिविधियां। सोचिए, जिस गली में दो कारों एक साथ नहीं निकल सकतीं, वहां डे केयर और बैंक कैसे चलेंगे? पार्किंग कहाँ होगी? मरीज की एंबुलेंस कहाँ खड़ी होगी? यह योजना कागज पर तो व्यवस्थित लगती है, जमीन पर जाम ही जाम आएगी।

**ग्रीन बेल्ट में भी दुकान का जुगाड़**-सबसे खतरनाक बात यह है कि ग्रीन बेल्ट और प्रतिबंधित क्षेत्र में आंतरिक संकरे मार्ग पर भी व्यवसाय को

नियमित करने का रास्ता खोला जा रहा है। भोपाल की पहचान तालाब और हरियाली है। यदि हरियाली की जमीन पर भी दुकान वैध हो गई तो शहर सांस कहां लेगा? यह तो पर्यावरण पर सीधा हमला है। जो परिसर खुद को घर बताकर बने थे, अब वही शोरूम बन गए हैं और अब उन्हीं को वैध करने के लिए मास्टर प्लान का सहारा लिया जा रहा है।

**सत्तर लाख का खेल**-छोटे व्यापारी के लिए प्रति, 1,556 रुपए प्रति वर्गफीट की दर से छोटा व्यापारी वैध नहीं हो पाएगा। यह दर तो बड़े इन्वेस्टर के लिए लगा रहे हैं, ताकि प्लान लागू होते ही पैसा भरकर वैध हो जाएं। **बारह मीटर की गली में अस्पताल का सपना**-नए ड्राफ्ट में सड़क की चौड़ाई से व्यवसाय तय किया गया है। 12 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर एक मंजिल पर डॉक्टर, वकील, इंजीनियर को बैठने की अनुमति, 12 से 18 मीटर पर बैंक, मेडिकल स्टोर और डे केयर सेंटर, 18 से 24 मीटर पर नर्सिंग होम, होटल, रेस्टोरेंट और कोचिंग, 24 से 30 मीटर पर सर्विस सेंटर और सारी मिश्रित गतिविधियां। सोचिए, जिस गली में दो कारों एक साथ नहीं निकल सकतीं, वहां डे केयर और बैंक कैसे चलेंगे? पार्किंग कहाँ होगी? मरीज की एंबुलेंस कहाँ खड़ी होगी? यह योजना कागज पर तो व्यवस्थित लगती है, जमीन पर जाम ही जाम आएगी। **ग्रीन बेल्ट में भी दुकान का जुगाड़**-सबसे खतरनाक बात यह है कि ग्रीन बेल्ट और प्रतिबंधित क्षेत्र में आंतरिक संकरे मार्ग पर भी व्यवसाय को

सुनें और सुनाएं। स्थानीय कलाकारों को पैसा और मंच दोनों दें। जब एक गोंडी चित्रकार को लगेगा कि उसकी कला बिककर रही है तो वह अपनी भाषा भी बचाएगा। तकनीक में अपनी भाषा को डालें, कीबोर्ड बनाएं, शब्दकोश बनाएं, वाक्यों का संग्रह बनाएं। तभी एआई हमारी भाषा सीखेगा और हमें उसकी बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ेगी। एआई बहुत तेज है, लेकिन संस्कृति तेज नहीं होती। वह धीरे-धीरे पनपती है, जैसे बरसात का पेड़ा। अगर हम बरगद को तेज बढ़ाने के लिए खींचेंगे तो वह टूट जाएगा। उसी तरह अगर हम अपनी भाषा, संस्कृति और परंपरा को बचाने के लिए पूरी तरह एआई पर निर्भर हो गए तो हम अपनी जड़ें ही खो देंगे। इसलिए जरूरी है कि हम तकनीक का उपयोग करें, लेकिन अपनी पहचान अपने हाथों में रखें। अपनी बोली को ज़िंदा रखना किसी मशीन का काम नहीं, बल्कि हम सबका कर्तव्य है।

( नईदुनिया संपादकीय डेस्क )

## तेज रफ्तार एआई और धीमी पड़ती अपनी बोली...



है तो एआई उसका अनुवाद कैसे करेगा? उस गीत में फसल की बात है, प्रेम की बात है, जंगल की बात है, वह सब एक साथ है। क्या एआई उस लय को पकड़ पाएगा? नहीं पकड़ पाएगा। इसी तरह गणगौर पर मालवा की महिलाएं जो गीत गाती हैं, उनमें जो विरह है, वह किसी ट्रांसलेशन मॉडल में नहीं है। हमारे कुम्हार की चाक पर जो कहानी घूमती है, हमारे बुनकर के करघे पर जो लोककथा बुनी जाती है, वह सब हमारी बोली में ही जिंदा है। बोली गई तो कला भी गई और कला गई तो पहचान भी गई।

आत्मनिर्भरता का मतलब क्या है? इसका मतलब यह नहीं है कि हम एआई का विरोध करें। विरोध करना मूर्खता होगी। एआई एक

ताकत है, लेकिन हमें उसके मालिक बनना है, उसके गुलाम नहीं। आत्मनिर्भरता का मतलब है कि हम अपनी भाषाओं का डेटा खुद बनाएं। हमारे स्कूलों में बच्चों को अपनी बोली में कहानी लिखने को कहा जाए। हमारे विश्वविद्यालयों में लोकगीतों को रिकॉर्ड किया जाए। हमारे युवा अपनी बोली के यूट्यूब चैनल, पांडकास्ट और ऐप बनाएं। सरकार सिर्फ हिंदी दिवस न मनाए, बल्कि बोली दिवस भी मनाए। जब हमारे पास अपना डेटा होगा तो हम एआई को अपनी शर्तों पर सिखा पाएंगे कि देखो, यह हमारी भाषा है, ऐसे बोली जाती है, इसमें इतना प्यार है। घर में किसी बोली बोलें, बच्चों से उसी में बात करें। त्योहारों को सिर्फ फोटो खिंचवाने का मौका न समझें, बल्कि उनके पीछे की कथा को अपनी भाषा में